E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2024; 6(2): 03-05
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 15-04-2024
Accepted: 20-05-2024

डॉ. गायत्री
राजनीति विज्ञान विभाग
एस.पी.सी. गवर्नमेंट कॉलेज,
अजमेर, राजस्थान, भारत।

रविन्द्र गुर्जर
पी.एचडी. शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, एस.पी.सी. गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर, राजस्थान, भारत।

Corresponding Author:
डॉ. गायत्री
राजनीति विज्ञान विभाग
एस.पी.सी. गवर्नमेंट कॉलेज,
अजमेर, राजस्थान, भारत।

भारतीय लोकतंत्र में जाति की राजनीति : प्रभाव एवं भूमिका

डॉ. गायत्री, रविन्द्र गुर्जर

DOI: https://doi.org/10.33545/26646021.2024.v6.i2a.350

सारांश
''संविधान द्वारा भारत में जाति निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष व्यवस्था कायम की गई है परन्तु हमारी राज व्यवस्था के सम्मुख प्रमुख चुनौती जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद आज भी है। हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ परन्तु आज भी हमारे राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन को कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो जातिवाद से प्रभावित न हो।

मूल शब्दः भारतीय लोकतंत्र, जाति की राजनीति, प्रभाव एवं भूमिका

प्रस्तावना

जातिप्रथा की उत्पति

जाति प्रथा की उत्पत्ति वैदिककाल में हुई, जिसके अनुसार चार वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र। ब्राम्हण धार्मिक और वैदिक कार्यो का संपादन करते थे। क्षत्रिय देश की रक्षा एवं शासन संचालन का कार्य करते थे। वैश्य कृषि एवं वाणिज्य का कार्य करते थे एवं शुद्र सेवा का कार्य करते थे। अपने मौलिक रूप में जाति प्रथा उपयोगी थी। यह श्रम विभाजन एवं कार्य कुशलता पर आधारित थी। इसने आर्थिक क्षेत्र में निपुणता का समावेश किया। एक जाति का पेशा उसी जाति में होता था पिता से पुत्र व्यवसाय प्राप्त कर उसी को अपने आजीविका का साधन बनाता था। प्रारंभ में जाति व्यवस्था कर्म पर आधारित थी जो बाद में विकृत होकर जन्म पर आधारित हो गई। जाति प्रथा में बाद में कठोरता आती गई और एक जाति से दूसरी जाति में अंत क्रिया असम्भव हो गई।

जाति व्यवस्था की विशेषताएँ :

- भारत में जाति ऐसे समुदाय है, जिनका अपना विकसित जीवन है और इसकी सदस्यता जन्म से ही निश्चित होती है,
- भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति जानता है और जातियों के पदसोपान में ब्राह्मण सबसे ऊपर माना जाता है.
- जातियों के आधार पर खान–पान और सामाजिक आदान–प्रदान में अंतराल था,
- गाँव तथा शहर में जाति के अधार पर पृथकता की भावना बनी रहती है.
- कुछ जातियाँ कतिपय विशेष प्रकार के व्यवसायों को अपना पुश्तैनी अधिकार समझती है,
- जातियों की परिधि में ही वैवाहिक आदान–प्रदान होता है और जातियों कई उपजातियों में विभक्त होती है। उपजातियों में भी वैवाहिक सीमाएँ है।

स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात संविधान और राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण से आधुनिक प्रभावों ने भारतीय समाज में धीरे–धीरे प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया बस्यक मताधिकार के आधार पर निर्वाचन प्रारम्भ हुआ और जातिगत संस्थाएँ एकाएक महत्वपूर्ण बन गई क्योंकि उनके पास भारी संख्या में मत थे और लोकतंत्र में सत्ता प्राप्ति हेतु इन मतो का मूल्य है।

परम्परावादी भारतीय समाज में आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं से एवं राजनीतिक आधुनिकीकरण से यह विचार किया गया था कि संस्था जति समाप्त हो जायेगी। परन्तु वयस्क मताधिकार के कारण जाति राजनीति शक्ति के रूप में उभरी है।

प्रो० कोठारी के शब्दो मे प्रथम कोई भी सामाजिक कभी भी पूर्णतया समाप्त नहीं हो सकता। अतः यह प्रश्न करना कि भारत में जाति का लोप हो रहा है. अर्थ शून्य है। द्वितीय जाति व्यवस्था आधुनीकरण और सामाजिक परिवर्तन में रुकावट नहीं डालता बल्कि उसको बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

प्रो० रूडोल्फ "भारत के राजनीतिक लोकतंत्र के संदर्भ में जाति यह धुरी है, जिसके माध्यम से नवीन

मूल्यों और तरीकों की खोज की जा रही है। यर्थाथ में जाति एक ऐसा माध्यम बन गई है. जिसके माध्यम से भारतीय जनता को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ा जा सकता है।"

राजनीति में जातिवाद का अर्थ :

राजनीति में जातिवाद का अर्थ है जाति का राजनीतिकरण अर्थात जाति को अपने दायरे में खीचकर राजनीति उसे अपने काम में लाने का प्रयत्न करती है। दूसरी और जाति को भी देश की व्यवस्था में भाग लेने का मौका मिलता है। नेता सत्ता प्राप्ति हेतु जाति का उपयोग करते है। जाति के रूप में उन्हें एक संगठन मिल जाता है।

जाति का राजनीतिक रूप :

हमारे राजनीतिज्ञ एक अजीब असमंजस्य की स्थिति में है, जहाँ एक ओर के जातिगत भेदभाव मिटाने की बात करते है। वही दूसरी ओर जाति के आधार पर वोट बटोरने की कला में निपुणता हासिल करना चाहते है।

परिचय

भारत वह देश है जहां विविधता में एकता पायी जाती है इसी कारण भारत को प्राचीन परंपरावादी, बहुभाषी और विभिन्न धर्मावलंबियों वाला देश कहा जाता है भारतीय समाज इस प्रकार श्रेणीक्रम समूहों में विभाजित है कि विभिन्न समूह परस्पर संबंधों को असमान समझे जाते हैं लेकिन एक ही समूह के सदस्य समान माने जाते हैं

भारतीय समाज की सबसे विशिष्ट एवं प्रमुख विशेषता जातीय सामाजिक स्तरीकरण है भारत में स्तरीकरण के आधार को जाति व्यवस्था के नाम से जाना जाता है भारत में जाति व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण का सबसे स्थायी और जटिल व्यवस्था है

जाति भारतीय सामाजिक व्यवस्था की ऐसी विशिष्ट और प्रमुख व्यवस्था है जिसका प्रदुभव समाज के व्यवस्थित संचालन के लिए हुआ था व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसकी जाति निश्चित हो जाती है भारतीय जनप्रतिनिधियों का यह अनुमान था कि स्वंतत्रता, समानता, सामाजिक न्याय तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना के साथ ही जाति व्यवस्था का प्रभाव शैन : शैनः कमजोर हो जाएगा परंतु ऐसा कही हुआ नहीं और जाती व्यवस्था ने भारतीय समाज में अपनी गहरी जड़े जमा ली जिसका एक स्वरुप मतदान व्यवहार में सीधे तौर पर देखा जा सकता है

योगेन्द्र सिंह मानते हैं कि सरांचनात्मक रूप से जाति व्यवस्था दो प्रवृतिया एक साय प्रदर्शित करती हैः एक खंडो में विभक्त और दूसरी समन्वित खण्डित यथार्थ के रूप में प्रत्येक जाति या उपजाति परस्पर विकर्षण, सामाजिक दूरी व सामाजिक असमानता को दर्शाती है किन्तु एक समन्वित व्यवस्था के रूप में जाति खंड जाजमानी प्रथा के माध्यम से पारस्परिकता के सिद्धांत द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं

संकेतांक – जाति, मतदान व्यवहार, सामाजिक व्यवस्था, स्तरीकरण

उद्देश्य :

1. लोकतंत्र में जाति की भूमिका का अध्ययन करना
2. जाति और राजनीति के संबंध पर अध्ययन करना
3. जाति और मतदान व्यवहार का विश्लेषण करना
4. जाति के सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण को समझना

शोध पद्धति – प्रस्तुत शोध द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है जिसमें व्याख्यात्मक शोध पद्धति का प्रयोग अनुभवमूलक अध्ययन पर किया गया है

भारत में जाति एवं राजनीति के मध्य आपसी संबंध को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं–

1. राजनीति में जातिवाद के प्रभाव को जाति का राजनीतिकरण कहा जा सकता है। लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत राजनीति, जाति के संगठन के माध्यम से अपना आधार दृढ़ करती हैं जाति ने राजनीति में अपनी भूमिका निर्वाह हेतु नवीन रूप धारण कर लिया है।
2. सभी राजनीतिक दल सिद्धांतः जातिवाद की निंदा करते हैं किंतु जातीय ध्रुवीकरण के माध्यम से सता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।
3. राजनीतिक दर्ता द्वारा प्रत्याशियों का चयन तथा सफलता की संभावना का आकलन जातीय मापदंडों से किया जाता है योग्यता व सेवा तत्वों की उपेक्षा की जाती है।
4. मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि सभी जातियों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाए।
5. जातिया सरकार की निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं इसका उदाहरण है अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण, मंडल आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का क्रियान्वयन।
6. प्रशासन में भी आरक्षण के माध्यम से जाति को महत्व प्रदान किया गया है।
7. राजनीतिक नेतृत्व का जनाधार केवल जातिगत आधार तक ही सीमित है।
8. जातीय संघर्ष से राजनीति के अंतर्गत हिंसा का प्रवेश हो गया है और जाति एक उपलाभ पदावली बन गई है।

भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका :

राजनीति पर जाति व्यवस्था का प्रभाव समय के साथ–साथ बढ़ रहा है लेकिन जाति व्यवस्था का रूप परिवर्तित होता रहता है। स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जाति का प्रभाव पहले की अपेक्षा बढ़ा है अतः भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का अध्ययन नियमानुसार किया जा सकता है–

1. जाति प्रधान राजनीतिक दलों का विकास–राजनीति के अंतर्गत सफलता प्राप्त करने के लिए जाति प्रधान राजनीतिक दलों का विकास हो रहा है। यह नेता की भावनाओं को उभार कर राजनीतिक लाभ उठाते हैं और उसी के आधार पर चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं जैसे लोकदल पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी आदि।
2. जाति के आधार पर चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवारों का चयन करना।
3. राजनीतिक दलों द्वारा जातिगत आरक्षण के माध्यम से हितों को पूरा करने की होड़।
4. मंत्रिमंडल के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व जैसे ब्राह्मण, जाट, राजपूत, कायस्थ, दलित व पिछड़े आदि।
5. निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका–जातीय संगठन अपने हितों के अनुसार निर्णय करने तथा अपने हितों के प्रतिकूल होने वाले निर्णयों को रोकने हेतु निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं।
6. जाति एवं प्रशासन–भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं के अलावा प्रशासन में भी जातिगत आरक्षण की व्यवस्था की गई है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण दिया गया है।
7. चुनाव प्रचार में जाति का सहारा–राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जाति का खुलकर प्रयोग करते हैं चुनाव के समय जातीय समीकरण बैठाए जाते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल क्षेत्र विशेष में जिस जाति का बाहुल्य है उसमें उसी जाति के बड़े नेता का चुनाव प्रचार हेतु भेजने का प्रयत्न करते हैं।
8. जाति के आधार पर राजनीतिक अभिजनों का उदय–जो

लोग जातीय संगठनों में उच्च पदों पर पहुंच गए हैं वे ही राजनीति में भी अच्छे स्थान प्राप्त करने में सफल हुए हैं ऐसे लोग राजनीति में चाहे खुलकर जातिवाद का सहारा ना लें फिर भी यह अपनी पृष्ठभूमि को नहीं भूलते। वे अपने जातीय हितों की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पैरवी करते रहते हैं।

जाति और राजनीति पर प्रमुख विचार :

रजनी कोठारी :

जातीय नेतृत्व द्वारा जातीय हितो या मुद्दों को उठाकर जाति में अपना समर्थन बढ़ाकर राजनीतिक लाभ उठाना ही जातिगत राजनीति है। अतः राजनीति में जातिवाद के प्रभाव को ''जातिगत राजनीति ''कहा जा सकता है। जातीय संघों अथवा संगठनों ने जातिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बढ़ाया है। इसके अंतर्गत क्षेत्र विशेष में कोई जाति विशेष राजनीतिक रूप से ज्यादा प्रभावशाली एवं शक्तिशाली होती है।

जातिगत राजनीति के प्रभाव :

जातिगत राजनीति के सकारात्मक प्रभाव :

1. सामाजिकता एवं एकता की भावना का विकास हुआ है।
2. जाति की राजनीति में लोगों में राजनीतिक सक्रियता पैदा की है।
3. जातीय सक्रियता के कारण समाज में उन जातियों का महत्व भी बढ़ा जो पहले राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से शक्ति विहीन थे ऐसी जातियों में भी राजनीतिक जागरूकता आई।

जातिगत राजनीति के नकारात्मक प्रभाव :

1. जातिगत राजनीति से बंधुत्व एवं एकता की भावना को हानि पहुंचती है अपने– अपने जाति हितों के संघर्ष के कारण वैमनस्यता पैदा होती है।
2. समाज के वातावरण में अमन चौन एवं शांति की जगह संघर्ष एवं अशांति पैदा होती है। जातीय केवल अपने हितों के लिए संघर्ष करती है।
3. जाति के आधार पर मतदान करने से योग्य व्यक्ति चुनाव हार जाते हैं। जीतने वाला व्यक्ति भी पूरे समाज के प्रति दायित्वबोध न समझ कर जातीय वफादारी पर ध्यान देता है यह देश एवं समाज दोनों के लिए घातक है।
4. जातिवाद भावना के कारण नागरिकों की श्रद्धा एवं भक्ति भी बढ़ जाती है लोग राष्ट्रीय हिर्ता के बजाय जाती हितों को प्राथमिकता देने लगते हैं।
5. जातिवाद के कारण से राजनीतिक दलों का निर्माण भी जाति के आधार पर होने लगता है।
6. जातिवादी सोच रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है जिसमें वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाता।
7. अल्पसंख्यक जातीय समुदाय के लोगों में असुरक्षा की भावना का विकास होता है।
8. जातिवाद लोकतांत्रिक भावना के विरुद्ध होता है यह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे लोकतंत्रीय मुल्यों को नुकसान पहुंचाता है।
9. वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा मिलता है।

राजनीति में जाति की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन :

राजनीतिक दलों ने जब जनता को सम्मोहित करने में अपने आप को असमर्थ महसूस किया तब राजनीति का खेल खेलने के लिए नेताओं ने राजनीति में जातिवाद का सहारा लिया। दलित शोषितों के उत्थान की आड़ में जातिवाद को राजनीति का अनिवार्य अंग बना दिया। जातिवाद के कारण जहां राज्य का उद्देश्य जनकल्याण का था उसको बदलकर रख दिया उसका वास्तविक उद्देश्य विभिन्न जातियों को संतुष्ट करने का रह गया। राजनीतिक दलों ने जातियों को वोट बैंक के रूप में हमेशा प्रयुक्त किया है।

अतः राजनीति में समाज व्यवस्था के दोषों को बढ़ावा देकर उसे परस्पर जाति संघर्ष एवं वैमनस्यता की आग में डाल दिया जिस पर राजनेता अपने हाथ सेंकते रहे हैं। जातिवाद में लोकतंत्र की धारणा के विरुद्ध काम किया है। जाति व्यवस्था ने राष्ट्र के एकीकृत स्वरूप के लिए संकट पैदा कर दिया है। फिर भी यह सत्य है कि जाति भारत के समाज की महत्वपूर्ण इकाई जिसकी उपेक्षा करना आसान नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि जाति के नकारात्मक स्वरुप के स्थान पर सकारात्मक स्वरूप की स्थापना की जाए। रुडोल्फ के अनुसार जाति व्यवस्था ने जातियों के राजनीतिकरण में सहयोग देकर परंपरा वादी व्यवस्था को आधुनिकता में डालने का कार्य किया है।

शोध निष्कर्ष :

जाति प्रथा किसी ना किसी रूप में संसार के प्रत्येक क्षेत्र में पाई जाती है बाबू जगजीवन राम के शब्दों में 'जाति भारतीय राजनीति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सत्यता है। एक सामान्य भारतीय अपना सब कुछ त्याग सकता है परंतु जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता है।

उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव कैंसर एवं एड्स जैसे भयंकर रोगों की तरह सर्वत्र फैल गया है जिसका निदान असंभव सा है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का मूल्यांकन करना अत्यंत जटिल कार्य है। यह केवल व्यक्ति–व्यक्ति के बीच खाई पैदा नहीं करती अपितु राष्ट्रीय एकता के मार्ग में भी बाधा उत्पन्न कर रही है। आज राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा जातिगत हितों को विशेष महत्व दिया जा रहा है, जिसके कारण हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो रही हैं।

अतः जातिवाद देश, समाज और राजनीति के लिए बाधक है लोकतंत्र व्यक्ति को इकाई मानता है न की किसी जाति या समूह को। जाति और समूह के आतंक से मुक्त रखना ही लोकतंत्र का आग्रह है।

संदर्भ ग्रंथ :

1. कोठारी, रजनी (1970), कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ओरियंट लॉगमन, नई दिल्ली।
2. सिंह, योगेन्द (1973), भारतीय परम्परा का आधुनिकीकरण, थॉमस प्रेस, नई दिल्ली।
3. श्रीनिवास (1962), एम.एन., कास्ट इन मॉडर्न इण्डिया एण्ड अदर ऐसेस, एशिया प्रकाशन, बम्बई।
4. रॉय, प्रणय (2019), भारतीय जनादेश : चुनावों का विश्लेषण
5. सरदेसाई, राजदीप (2015) 2014 का चुनाव जिसने भारत को बदल दिया, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
6. शर्मा, डी.आर. (2023), भारतीय शासन एवं राजनीति, रावत प्रकाशन, जयपुर।
7. जोन्स, डब्ल्यू मौटिस, (1967) भारतीय शासन एवं राजनीति, ब्लैकस्थान प्रकाशन, दिल्ली।